(1) यह अधिनियम भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

(2) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(3) राज्य सरकार के मुख्य सचिवों से पर्याप्त बजट संबंधी प्रावधानों सहित अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरु करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(4) दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए इस अधिनियम की टाकिंगइबुक तैयार की गई है।

(5) विकलांगों के पुनर्वासन में लगे हुए 400 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को इस अधिनियम की एक प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भेजी गई है।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा मानीटरिंग करने के लिए "विकलांग व्यक्ति मुख्य आयुक्त" के पद का सृजन किया जा रहा है।

इस्पात उत्पादन में गैर-सरकारी निवेश

477. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र द्वारा इस्पात परियोजनाएं लागू की जा रही हैं/लागू की जाने वाली हैं और उनकी संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) लोहा और इस्पात उद्योग को स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय शर्तों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया है। उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर निवेश करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत 15 इस्पात परियोजनाएं निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं/की जाएंगी। इस समय सरकारी क्षेत्र की किसी नई इस्पात परियोजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन 15 संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

आंध्र प्रदेश	2	गुजरात	1
कर्नाटक	3	महाराष्ट्र	4
मध्य प्रदेश	3	तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	1		

Benefits generated from Rural Employment Schemes

478. SHRI G.G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased tostate:

(a) whether it is a fact that rural employment schemes have not generated commensurating benefits in proportion to amount spent on the schemes; and

(b) the nature and size of unemployment at present in rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATIOIN) (SHRI VILAS BABURAO MUTTEMWAR): (a) and (b) No, Sir. Rural Wage Employment Programmes such as the Jawahar Rozgar Yojana and the Employment Assurance Scheme have been successful in generating employment in the rural areas. Under these two programmes 1225.66 million mandays of employment was generated during the year 1994-95 corresponding to which an expenditure of Rs. 5503.78 crores was incurred. During the current year (1995-96) 694.44 million mandays of employment has been generated under these two schemes (as on December 31, 1995) against which an expenditure of Rs. 3415.85 crores has been incurred. It may be mentioned that these schemes are targeted at the rural poor who are below the poverty line, a large majority of whom are landless labourers. Due to seasonal factors affecting the agricultural